नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग

उ0प्र0 शासन का

वर्ष - 2015-16 के बजट

हेतु

कार्यपूर्ति दिग्दर्शक (परफार्मेंस)

बजट व वार्षिक रिपोर्ट

नगरीय रोज़गार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

संदेश

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 के बजट में शहरी गरीबों के जीवन स्तर में सुधार लाने तथा उन्हें रोजगार मुहैया कराने हेतु एवं उनकी सामाजिक और आर्थिक तरक्की के लिए नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग द्वारा विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही हैं। वर्तमान सरकार की प्राथमिकताओं में यह वचनबद्धता है कि विकास की जरूरत तो सभी को है, परन्तु उन्हें ज्यादा है, जो अत्यन्त पिछड़े हैं। इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक पाया गया कि विभाग द्वारा समाज के अत्यन्त कमजोर एवं पिछड़ों के लिए, विशेष रूप से जो मलिन बस्तियों में निवास कर रहे हैं, उनके उत्थान के लिए विशेष कार्यक्रम चलाये जायें। ऐसी योजनाओं, जो समाज को एक नई दिशा देंगी, जिनमें इन्सान को इन्सान का दर्जा दिया जा सके, पर यह सरकार संजीदगी से कार्य कर रही हैं। हमारी यह पहल यदि असमानता को पूर्ण रूप से मिटा न सके, तो कम अवश्य कर सकेगी।

राज्य सरकार द्वारा शहरी निर्धन अल्पसंख्यक व अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ी जाति के नागरिकों को बेहतर जीवन-यापन के लिए आसरा आवासीय योजना, मेहनतकश रिक्शा चालकों को मोटर/बैट्री चालित अत्याधुनिक रिक्शा को उपलब्ध करा कर मालिकाना हक, मलिन बस्तियों में अवस्थापना सुविधाओं हेतु इंटर लाकिंग सड़क, नाली आदि की योजना संचालित की जा रही है। उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2015-16 में समुचित बजट प्रावधान किया जा रहा है।

राजीव आवास योजना में प्रदेश के 21 शहरों को चयनित कर यह योजना संचालित की जा रही है तथा समस्त जिला मुख्यालयों सहित 1 लाख से अधिक आबादी वाले कुल 61 शहरों को योजना में शामिल करने के लिये प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है।

भारत सरकार द्वारा संचालित नई योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) के तहत शहरी गरीबों को व्यक्गित एवं समूह में ऋण उपलब्धता, शहरी आजीविका केन्द्रो का निर्माण, शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण, शहरी बेघरों हेतु आश्रय का निर्माण, शहरी पटरी दुकानदारों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु योजनाबद्ध रूप से उनके विकास हेतु व्यवस्थित रूप से कार्य किये जायेंगे।

आम गरीब व्यक्ति के हित में उनकी अपेक्षानुसार बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु यह विभाग प्रतिबद्ध है।

मोहम्मद आज़म खाँ
मंत्री
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग,
उ0प्र0 शासन।

प्राक्कथन

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग द्वारा वर्ष 2015–16 में किये ग़ये विभिन्न कार्य–कलापों की पुस्तिका प्रकाशित की जा रही है।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग का कार्यपूर्ति आय–व्ययक 2015–16 प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा नगरीय मलिन बस्तियों के विकास कार्यक्रमों से सम्बद्ध केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभागों में कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय–व्ययक (परफार्मेन्स बजट) तैयार किये जाने की संस्तुति पर आधारित है। नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग द्वारा संचालित अलग–अलग योजनाओं यथा– राष्ट्रीय शहरी अजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0), राजीव आवास योजना, आसरा योजना, रिक्शा योजना, अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों व मलिन बस्तियों में इण्टरलॉकिंग, नाली निर्माण आदि अवस्थापना सुविधायें, शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बी0एस0यू0पी0) तथा एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आई0एच0एस0डी0पी0) आदि योजनायें संचालित की जा रही हैं। इस कार्यपूर्ति दिग्दर्शक में विभाग द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यक्रमों एव भावी योजनाओं का विवरण भी प्रस्तुत किया गया है।

मुझे आशा है कि इस कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय–व्यय के संदर्भ में विभाग के कार्यक्रमों में सुधार, संशोधन एवं परिमार्जन हेतु उन्हें और प्रभावी तथा जनोपयोगी बनाने के उद्देश्य से विधान मण्डल के माननीय सदस्यों के सुझाव अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होंगे।

अतः इस प्रयोजन हेतु विधान मण्डल के माननीय सदस्यों के सुझावों का नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग में सदैव स्वागत है।

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव,
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग,
उ0प्र0 शासन।

अनुक्रमाणिका

1.	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा संचालित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण	7 -14
2.	वित्तीय आवश्यकतायें: कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों का वर्गीकरण	15 -16
3.	परफार्मेंस बजट (कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक) 2015-2016	17
4.	वित्तीय साधनों के स्रोत	18
5.	परफार्मेंस बजट (कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक) 2015-2016 गत तीन वर्षो के वित्तीय/भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियां तथा वर्ष 2015-2016 के प्रस्तावित विवरण	19
6.	गत चार वर्षो में शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में लाभार्थियों तथा मानव दिवसों के भौतिक लक्ष्यों/उपलब्धियों का विवरण	20

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा संचालित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

उत्तर प्रदेश में राज्य स्तर पर नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के अधीन राज्य स्तर पर राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) का गठन नोडल एजेन्सी के रूप में किया गया है। यह एजेन्सी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत 20 नवम्बर, 1990 से पंजीकृत है। जनपद स्तर पर जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) स्थापित किए गये हैं। इनके माध्यम से शहरी गरीबों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। जनपद के नगरीय विकास अभिकरण के पदेन अध्यक्ष संबंधित जिलाधिकारी हैं। जनपद के समस्त नगर निकायों के अध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नगरीय निर्धनों के सर्वांगीण उत्थान की दिशा में राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) के माध्यम से मुख्यतः निम्न योजनायें संचालित की जा रही हैं–

1 आसरा योजना (आवासीय भवन)।
2 प्रदेश के शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों व मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण, जल निकासी एवं अन्य सामान्य सुविधाओं का निर्माण।
3 मोटर बैटरी चालित रिक्शा वितरण योजना।
4 नगरीय क्षेत्र में एस0सी0एस0पी0 मद के बजट अनुदान से अनुसूचित जाति बाहुल्य मलिन बस्तियों के विकास की योजना।
5 राजीव आवास योजना।
6 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना (एन0यू0एल0एम0)
7 राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान की रामपुर नगर में स्थापना।
8 एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम।
9 शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं।

उपर्युक्त योजनाओं के संबंध में विस्तृत विवरण इस प्रकार है :–

1–आसरा योजना (आवासीय भवन) –

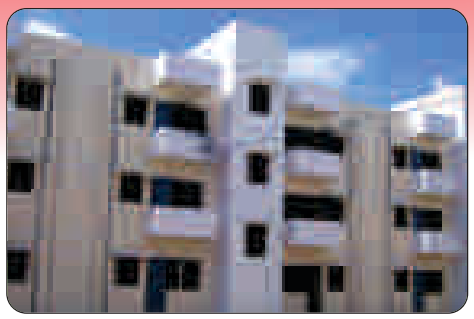

प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 में नवीन योजना आरम्भ कर शहरी क्षेत्रों में अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा नगरीय मलिन बस्तियों में कम लागत के रिहायशी मकान चयनित पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराने हेतु शहरी गरीबों को आवासीय सुविधा की तंगी के समाधान हेतु उनके जीवन स्तर में बदलाव और सामाजिक परिवेश में सुधार हेतु आसरा योजना आरम्भ की गयी।

इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 में रू0 335.67 करोड़ आय–व्ययक का प्रावधान किया गया है, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्श 2014–15 में अद्यतन 6883 आवासों की परियोजना हेतु रू0 185.04 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है, शेष स्वीकृतियां जारी होने की प्रकिया में हैं एवं आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए रू0 300.00 करोड़ का आय–व्ययक प्रावधान प्रस्तावित है, जिससे लगभग 7000 आवासहीन लाभार्थी लाभान्वित होगें।

2–प्रदेश के शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण, जल निकासी एवं अन्य सामान्य सुविधाओं का निर्माण –

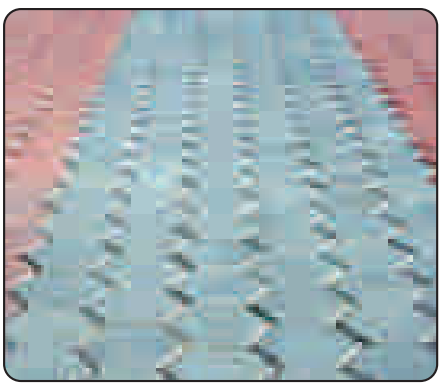

प्रदेश सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य एवम् अन्य मलिन बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं के दृष्टिगत सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली, जल निकासी, पेयजल, मार्ग प्रकाश व्यवस्था आदि मूलभूत सुविधायें मुहैया कराने के लिये यह योजना संचालित की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत पिछड़े मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों एवं मलिन बस्तियों में विकास कार्य कराये जाने की प्राथमिकता है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय व्ययक में रू0 375.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिसके सापेक्ष जनपदों की नगर निकायों हेतु अद्यतन रू0 349.55 करोड़ की धनराशि शासन से स्वीकृत हुयी एवं कार्य प्रगति पर है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में उक्त कार्य हेतु रू0 310.00 करोड़ का आय–व्ययक प्रावधान प्रस्तावित है।

3– मोटर बैटरी चालित रिक्शा वितरण योजना –

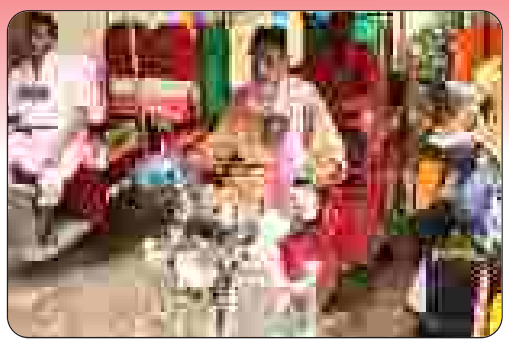

प्रदेश के महानगरों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायत क्षेत्रों में मानव चालित रिक्शा कम दूरी के आवागमन का प्रमुख एवं सर्व सुलभ साधन है। इस कार्य में अधिकांश रिक्शा चालक समाज के निर्धन एवं कमजोर तबके के साधनहीन समुदाय के हैं। मानव चालित रिक्शा अत्यधिक श्रमसाध्य होने के कारण रिक्शा चालकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम

स्वरूप वे गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। रिक्शा चालकों को हाड़तोड़ शारीरिक श्रम से राहत दिलाए जाने व उनकी आयवृद्धि कर उनके जीवन स्तर में सुधार हेतु रिक्शा चालकों को मुफ्त मोटर/बैटरी चालित/इ–रिक्शा देने की योजना संचालित है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में इस योजना हेतु रू0 300.00 करोड़ का आय–व्ययक प्रावधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में इस योजना हेतु रू0 300.00 करोड़ का आय– व्ययक प्रावधान प्रस्तावित है।

4–नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जाति बाहुल्य मलिन बस्तियों के विकास हेतु एस0सी0एस0पी0 मद में राज्य बजट से अनुदान –

प्रदेश के 630 स्थानीय निकायों में स्थित अनुसूचित जाति बाहुल्य (40 प्रतिशत से अधिक) मलिन बस्तियों में जल एवं मल निकासी, पेयजल, बरसाती नाला और सड़क आदि आधारभूत सुविधाए मुहैया कराने के लिय राज्य बजट से वित्तीय वर्ष 2014–15 के एस0सी0एस0पी0 मद में से रू0 2000.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया था जिसके सापेक्ष अद्यतन रू0 1346.21 लाख स्वीकृत किया गया है। इस योजना में शहरी क्षेत्र की अनुसूचित जाति बाहुल्य मलिन बस्तियों का विकास किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में एस0सी0एस0पी0 मद में से रू0 20.00 करोड़ का आय–व्ययक प्रावधान प्रस्तावित है।

5–राजीव आवास योजना –

राजीव आवास योजना का मूल उद्देश्य शहरों को स्लम मुक्त किया जाना है। इसके अन्तर्गत स्लम में निवासित आबादी को किफायती आवास मुहैया कराये जाने के साथ ही बुनियादी सुविधाएं और सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराया जाना है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रदेश में चयनित 21 नगरों में योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में 5 लाख या अधिक आबादी वाले शहरों में केन्द्रांश व राज्याश का अनुपात क्रमशः 50:50 है तथा 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों में केन्द्रांश व राज्यांश का अनुपात क्रमशः 75:25 है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में योजनान्तर्गत रू0 200.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। मथुरा, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, मेरठ, वाराणसी, गाजियाबाद, अलीगढ़, गोरखपुर, झॉसी, इटावा व इलाहाबाद की परियोजनाए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कर दी गयी है। मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद व मेरठ की परियोजनाओं की राज्य से वित्तीय स्वीकृति निर्गत हो चुकी है। शेष की वित्तीय स्वीकृति शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है। सहारनपुर, बरेली व शाहजहॉपुर की परियोजनाए भारत सरकार में स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि लाभार्थियों की दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुये राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी अंश एवं निकाय अंश स्वयं वहन करने का निर्णय लिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में योजनान्तर्गत रू0 200.00 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

6–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना (एन0यू0एल0एम0) –

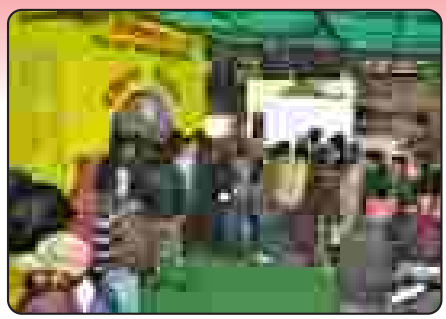

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना 31 मार्च, 2014 को भारत सरकार द्वारा समाप्त कर उसके स्थान पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) प्रदेश के चयनित 82 शहरों में वर्ष 2014–15 में प्रारम्भ की गयी है। योजना में एसजेएसआरवाई के अनुरूप केन्द्रीय अनुदान 75 प्रतिशत एवं राज्यांश 25 प्रतिशत निर्धारित है। योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी गरीब परिवारों को जमीनी स्तर पर संस्थाओं के माध्यम से उनको लाभप्रद स्व0 रोजगार और कौशल के आधार पर वेतन युक्त रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बना कर उनकी गरीबी और असुरक्षा को दूर करना है, जिससे उनकी जीविका में दीर्घकालीन सुधार हो सके। भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत शहरी बेघर एवं पटरी दुकानदारों पर विशेष ध्यान देते हुए उनके कार्य के लिए उपयुक्त स्थल, ऋण एवं कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराकर उनकी जीविका संबंधी समस्याओं का निवारण किया जाना है। एन0यू0एल0एम0 में वित्तीय वर्ष 2014–15 में रू0 रू0 96.66 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।योजनान्तर्गत वार्षिक कार्य योजना 2014–15 तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के मुख्य उपघटक निम्नवत् हैं –

1. सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास–इस उपघटक के अन्तर्गत शहरी गरीबों को स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) संगठित कर उनकी वित्तीय और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता का प्रावधान है। स्वयं सहायता समूहों को आवर्ती निधि के रूप में अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा ताकि वह अपने कार्यकलापों को चला सके।

उपघटक के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में अद्यतन 24 शहरी आजीविका केन्द्र के प्रस्ताव स्वीकृत एवं 227 स्वयं सहायता समूहों का गठन भी कर लिया गया है।

2. क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण–इस उपघटक के अन्तर्गत मिशन के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर एवं शहर स्तर पर विशेषज्ञों एवं अन्य कार्यकर्ताओं को रखे जाने एवं उनके प्रशिक्षण इत्यादि की व्यवस्था की गई है।

3. कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार–इस उपघटक के अन्तर्गत शहरी गरीबों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा ताकि वे स्वरोजगार उद्यम स्थापित कर सके अथवा वेतन युक्त रोजगार प्राप्त कर सकें।

4. स्वरोजगार कार्यक्रम–इस उपघटक के अन्तर्गत शहरी गरीबों को व्यक्तिगत एवं समूह में उद्यम स्थापित करने के लिये बैंक ऋण के ब्याज पर सब्सिडी अनुदान प्रदान किये जाने का प्रावधान है। उपघटक के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में अद्यतन 572 व्यक्तियों को ऋण वितरित किया जा चुका है।

5. शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता–इस उपघटक के अन्तर्गत पथ विक्रेताओं के सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण, विक्रय अनुकूल आयोजना, विक्रेता बाजारों का विकास, पथ विक्रेताओं को स्वरोजगार घटक के अन्तर्गत ऋण उपलब्ध कराना, कौशल विकास एवं सरकार की अन्य विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध सहायता को पथ विक्रेताओं तक पहुँचाने की योजना है।

6. शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना–इस उपघटक के अन्तर्गत शहरी बेघर लोगों को बुनियादी सुविधा युक्त आश्रय प्रदान करना है। उपघटक के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में अद्यतन निकायों से प्राप्त प्रस्तावों में से 42 प्रस्ताव स्वीकृत तथा शेष पर कार्यवाही प्रक्रिया में है।

   वित्तीय वर्ष 2015–16 में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) हेतु रू0 209.50 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

7–राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान की रामपुर नगर में स्थापना –

प्रदेश स्तर पर नगरीय निकयों की विभिन्न योजनाओं में सेवायोजित कर्मियों तथा लाभार्थियों की क्षमता के विकास हेतु राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना रामपुर नगर में किया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में उक्त कार्य हेतु रू0 10.00 करोड़ का आय–व्ययक प्रावधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में उक्त कार्य हेतु रू0 20.00 करोड़ का आय–व्ययक प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

8–एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) –

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2005–06 से 'एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम' प्रारम्भ किया गया है । यह योजना कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, व मथुरा नगरों को छोड़कर प्रदेश के शेष समस्त निकायों में लागू है। योजना का उद्देश्य शहरी मलिन बस्तियों में आवास और अवस्थापना सुविधाओं का समेकित विकास करना है । इस योजना में 80 प्रतिशत धनराशि केन्द्रीय अनुदान के रूप में प्राप्त होती है, शेष 20 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है, जिसमें 10/12 प्रतिशत लाभार्थी अंश सम्मिलित है।

आई0एच0एस0डी0पी0योजनान्तर्गत रू. 671.15 करोड़ के प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के सापेक्ष 37818 आवासों पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिसमें 19866 आवास पूर्ण कर लाभार्थियों को आवंटित किये जा चुके है। परियोजनाओं में मूल्यवृद्धि के फलस्वरूप इनको पूर्ण किए जाने हेतु उ0 प्र0 शासन द्वारा शहरी गरीबों के हितो को ध्यान में रखते हुए निर्माणाधीन आवासों एवं आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को प्रदेश सरकार के बजट से पूर्ण कराने का निर्णय लिया गया है।

योजना की मिशन अवधि मार्च, 2012 तक निर्धारित थी। भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत अधूरे कार्य को पूर्ण करने हेतु योजनावधि मार्च 2015 तक बढ़ा दी गयी है।

योजना को पूर्ण करने हेतु समय विस्तार के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु रू0 0.02 लाख का टोकन बजट प्रस्तावित किया गया है।

9– शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बी.एस.यू.पी.) –

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2005–06 से प्रदेश के चयनित नगरों, लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ तथा मथुरा में राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं योजना प्रारम्भ की गयी है। इस योजना का उद्देश्य मलिन बस्तियों में

आवास और अवस्थापना सुविधाओं को उपलब्ध कराना है। मथुरा नगर को छोड़कर, इस योजना के अन्तर्गत परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अंश केन्द्र सरकार द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत अंश राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है जिसमें लाभार्थी अंश भी सम्मिलित है। मथुरा नगर के लिए परियोजना लागत का 80 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा तथा शेष 20 प्रतिशत अंश राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है, जिसमें लाभार्थी अंश भी सम्मिलित है।

योजना की मिशन अवधि मार्च, 2012 तक निर्धारित थी। भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत अधूरे कार्य को पूर्ण करने हेतु योजनावधि मार्च 2015 तक विस्तारित की गयी है। योजनाओं को पूर्ण करने हेतु मूल्यवृद्धि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है।

बी0एस0यू0पी0 योजनान्तर्गत प्राप्त रू.1214.25 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र के सापेक्ष 45599 आवासों पर निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। जिसमें 36717 आवास पूर्ण कर लाभार्थियों को आवंटित किये जा चुके है।

योजना को पूर्ण करने हेतु समय विस्तार के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु रू0 0.02 लाख का टोकन बजट प्रस्तावित किया गया है।

तालिका -1

वित्तीय आवश्यकतायें: कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों का वर्गीकरण

रूपये लाख में

क्रम0सं0	अनुदान	मुख्य लेखा	कार्यक्रम	आय व्ययक 2013–14			आय व्ययक 2014–15			आय व्ययक अनुमान 2015–16		
	सं0	शीर्षक		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	37	2230	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना(योजना 31.03.2014 से समाप्त)	2425.26		2425.26			0.00			0.00
2		2230	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) वित्तीय वर्ष 2014–15 से आरम्भ	0.00		0.00	5000.00		5000.00	14100.00		14100.00
3		2230	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत राज्य स्तर पर एक प्रकोष्ठ का गठन	6.20		6.20	6.80		6.80	6.80		6.80
4		2217	शुष्क शौचालय परिवर्तन हेतु	750.00		750.00	0.00		0.00			0.00
5		4217	एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)	6937.50		6937.50	6575.00		6575.00	0.01		0.01
6		4217	शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी)	10950.00		10950.00	10950.00		10950.00	0.01		0.01
7		4216	राजीव आवास योजना	5000.00		5000.00	10000.00		10000.00	12000.00		12000.00
8		2217	अर्बन स्टैटिस्टिक्स फॉर एच.आर. एण्ड एसैसमैन्ट (यू.एस.एच.ए.)	0.01		0.01	0.00		0.00			0.00
9		4216	आसरा योजना (आवासीय भवन)	20000.00		20000.00	21567.00		21567.00	18000.00		18000.00
10		2230	रिक्शा योजना	18000.00		18000.00	18000.00		18000.00	18000.00		18000.00
11		2217	प्रदेश की अल्पसंख्यक बाहुल्य मलिन बस्तियों में मूलभूत सुविधायें	18750.00		18750.00	25000.00		25000.00	18700.00		18700.00
12		4250	अल्प संख्यक एवं निर्धन शहरी गरीबों हेतु लघु व्यापार केन्द्र (योजना एसजेएसआरवाई से लिक होने के कारण वित्तीय वर्ष 2014–15 से समाप्त)	100.00		100.00	0.00		0.00			0.00
13		4217	रामपुर में राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान	25.00		25.00	1000.00		1000.00	2000.00		2000.00
			योग	82943.97	0.00	82943.97	98098.80	0.00	98098.80	82806.82	0.00	82806.82

तालिका -1

वित्तीय आवश्यकतायें: कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों का वर्गीकरण

रूपये लाख में

क्रम0सं0	अनुदान	मुख्य लेखा	कार्यक्रम	आय व्ययक 2013–14			आय व्ययक 2014–15			आय व्ययक अनुमान 2015–16		
	सं0	शीर्षक		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	83	2230	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना(योजना 31.03.2014 से समाप्त)	1213.00		1213.00	0.00		0.00			0.00
2		2230	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) वित्तीय वर्ष 2014–15 से आरम्भ	0.00		0.00	4666.00		4666.00	6500.00		6500.00
3		4217	एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)	6937.00		6937.00	6550.00		6550.00	0.01		0.01
4		4217	शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी)	10950.00		10950.00	10950.00		10950.00	0.01		0.01
5			अनुसूचित जाति सब प्लान, (राज्य सेक्टर)			0.00			0.00			0.00
6		2217	अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं	1000.00		1000.00	2000.00		2000.00	2000.00		2000.00
7		2217	शुष्क शौचालय परिवर्तन हेतु	750.00		750.00	0.00		0.00			0.00
8		4216	आसरा योजना (आवासीय भवन)	18907.69		18907.69	12000.00		12000.00	12000.00		12000.00
9		2230	रिक्शा योजना	4793.40		4793.40	12000.00		12000.00	12000.00		12000.00
10		2217	मलिन बस्तियों में मूलभूत सुविधायें	18750.00		18750.00	12500.00		12500.00	12300.00		12300.00
11		4250	निर्धन शहरी गरीबों हेतु लघु व्यापार केन्द्र	100.00		100.00	0.00		0.00			0.00
12		4216	राजीव आवास योजना	5000.00		5000.00	10000.00		10000.00	8000.00		8000.00
			योग	68401.09	0.00	68401.09	70666.00	0.00	70666.00	52800.02	0.00	52800.02
1	81		राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.)							350.00		350.00
			महायोग	151345.06	0.00	151345.06	168764.80	0.00	168764.80	135956.84	0.00	135956.84

तालिका -2

परफार्मेंस बजट (कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक)2015-2016

(रू0 लाख में)

क्रम	योजनायें	2012–2013				2013–2014				2014–2015 (जनवरी,2015 तक)				2015–2016 (प्रस्तावित)	
		केन्द्रांश	अवमुक्त धनराशि	राज्यांश	अवमुक्त धनराशि	केन्द्रांश	अवमुक्त धनराशि	राज्यांश	अवमुक्त धनराशि	केन्द्रांश	अवमुक्त धनराशि	राज्यांश	अवमुक्त धनराशि	केन्द्रांश	राज्यांश
1	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	9337.26	4668.63	14499.79	1555.38	9348.00	9393.43	3638.26	3077.76						
2	राज्य स्तर पर एक प्रकोष्ठ का गठन			5.76	5.76	0.00	0.00	6.20	6.00			6.80	6.80		6.80
3	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) वित्तीय वर्ष 2014–15 से आरम्भ											9666.00			20950.00
4	एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)			35227.00	13064.66			13874.50	13874.50			13100.00			0.02
5	शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी)			52840.00	17221.45			21900.00	21900.00			21900.00			0.02
6	राजीव आवास योजना			733.00	55.49			10000.00	6860.07			20000.00	4780.94		20000.00
7	आसरा योजना			10000.00	10000.00			38907.69	4786.04			33567.00	15240.34		30000.00
8	रिक्शा योजना			10000.00	10000.00			22793.40				30000.00			30000.00
9	अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं			1850.00	1104.88			1000.00	999.84			2000.00	904.38		2000.00
10	प्रदेश की अल्पसंख्यक बाहुल्य मलिन बस्तियों में मूलभूत सुविधायें			10000.00	10000.00			37500.00	32922.97			37500.00	31885.08		31000.00
11	रामपुर में राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान			525.00				25.00	0.00			3000.00			2000.00
12	अर्बन स्टैटिस्टिक्स फॉर एच.आर. एण्ड एसैसमैन्ट (यू.एस.एच.ए.)			60.22	60.21			0.00	0.00						
13	अल्प संख्यक एवं निर्धन शहरी गरीबों हेतु लघु व्यापार केन्द्र (योजना एसजेएसआरवाई से लिंक होने के कारण वित्तीय वर्ष 2014–15 से समाप्त)			200.00	100.00			200.00	0.00						
14	शुष्क शौचालय परिवर्तन हेतु			10.00				1500.00	0.00						
	योग–	9337.26	4668.63	135950.77	63167.83	9348.00	9393.43	151345.05	84427.18	0.00	0.00	170739.80	52817.54	0.00	135956.84

तालिका –3

वित्तीय साधनों के स्रोत

रूपये लाख में

क्र0सं0	अनुदान सं0	मुख्य लेखा शीर्षक	आय व्ययक 2013–14			आय व्ययक अनुमान 2014–15			पुनरीक्षित 2014–15			आय व्ययक अनुमान 2015–16		
			आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	37	2230,2217,	41925.26	—	41925.26	51673.80	—-	51673.80	48006.80	—	48006.80	50806.80	—	50806.80
2	83	2230,2217	41713.00	—	41713.00	31166.00	—-	31166.00	31166.00	—	31166.00	32800.00	—	32800.00
3	37	4217	17912.50	—	17912.50	20500.00	—-	20500.00	18525.00	—	18525.00	2000.02	—	2000.02
4	83	4217	17887.00	—	17887.00	17500.00	—-	17500.00	17500.00	—	17500.00	0.02	—	0.02
5	37	4216,4250	25100.00		25100.00	31567.00	—-	31567.00	31567.00	—	31567.00	30000.00	—	30000.00
6	83	4216,4250	25100.00		25100.00	22000.00	—-	22000.00	22000.00	—	22000.00	20000.00	—	20000.00
	81											350.00	—	350.00
	योग		169637.76		169637.76	174406.80		174406.80	168764.80		168764.80	135956.84		135956.84

तालिका- 4

परफार्मेस बजट (कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक) 2015-2016 गत तीन वर्षो के वित्तीय/भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियां तथा वर्ष 2015-2016 के प्रस्तावित विवरण

धनराशि रू0 लाख में
संख्या लाख में

		2012–2013				2013–2014				2014–2015 (जनवरी,2015)				2015–2016 (प्रस्तावित)	
क्रम	योजनायें	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य
	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	12449.68	4749.87	0.81	0.26	14590.46	11568.35	1.25	1.17						
	राष्ट्रीय शहरी अजीविका मिशन (एन.यू. एल.एम.)									9666.00	785.68	1.15	0ण01	20950.00	1.20

उपरोक्त आंकडे केन्द्रांश एवं राज्यांश को जोडते हुए दर्शाये गये है ।

तालिका- 5

गत चार वर्षों में शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में लाभार्थियों तथा मानव दिवसों के भौतिक लक्ष्यों/उपलब्धियों का विवरण

(संख्या लाख में)

क्रम	मदें	2011–2012			2012–2013			2013–2014			2014–2015(जनवरी,2015)			2015–2016
		लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	प्रस्तावित
				%			%			%			%	
1.	लाभार्थी	0.92	0.39	42.39	0.81	0.26	32.10	1.25	1.17	93.60	1.15	0.01	0.87	1.20
2.	मानव दिवस	9.73	2.88	29.60	9.88	1.38	13.97							